गवर्नमेंट के लिये है कि 24 घंटे के अंदर सरकार अपना जवाब दे। आपकी बात ठीक है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन 24 घंटे तक इन पर काले बादल छाये रहें, यहीं ये पसंद करते हैं तो यह इनका दुर्भाग्य है।

श्री सभापति: अब आप जाने दीजिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): अब आप कृपया शांत रहिये, पूछने दीजिये।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर आप कहते है कि शांत रहिये तो यही स्वागत की बात है।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Losses incurred by G.I.C.

*1. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the General Insurance Corporation has been incurring heavy losses every year due to under-writing losses;

(b) whether it is also a fact that the General Insurance Corporation has failed as a holding company to create competition among its four subsidiaries; and

(c) if so, what are the details thereof and what remedial steps are being taken it this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. It is not correct to say that the General Insurance Corporation of India (GIC) has been incurring heavy losses every year. On the other hand, the GIC has earned overall net profits every year, ever since its formation in 1973. It has also earned underwriting profits almost every year barring 1984, 1986, 1988-89 (for 15 months) and 1990-91. The underwriting losses in these four years were Rs. 39.01 Crores, Rs. 2.15 Crores. Rs. 38.88 Crores and Rs. 33.11 Crores respectively. Even in these four years, the Corporation has earned net profits amounting to Rs 12.89 Crores, Rs. 52.62 Crores, Rs. 69.35 Crores and Rs. 88.68 Crores respectively.

(b) No, Sir. It is not correct to say that as a holding company, the GIC has failed to generate competition among the four subsidiary companies. On the other hand, the four subsidiary companies are operating all over the country in competition with each other.

(c) Does not arise.

श्री राम अवधेश सिंह: मान्यवर, यह इस सत्र का पहला सवाल है और वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वित्त मंत्रालय के अन्दर जो डायरेक्ट एजेंसीज़ हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज और इनश्योरेंस कम्पनीज़ हैं, वह किस ढंग से काम करती हैं और किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करती हैं, कैसे निजी कम्पनियों से मिल कर के देश के पैसे को लूटती और लुटवाती हैं, इसका एक पक्का उदाहरण इनश्योरेंश कम्पनीज़ के घाटे का है जो बैंकिंग तथा इनश्योरेंस कम्पनीज़ के अन्दर राइटिंग आफ बेड डेट्स के नाम में होता है। इसी पर यह मेरा सवाल है। माननीय वित्त राज्य मंत्रीय जी की ओर से जो जवाब आया है, वह बहुत ही असंतोषजनक जवाब है। इसको जवाब नहीं कहा जा सकता है। हमने यह सवाल पूछा है कि कितनी हानि है अंडरराइटिंग आफ लोन से, कितना लॉस होता है। तो इस में दो तरह की हानि होती है। एक तो इनश्योरेंस कंपनीज के जो दावे दिये जाते हैं जैसे पार्टी का नुकसान हुआ तो वह दावे के रूप में क्षतिपूर्ति करती है इसलिए हानि होती है और दूसरी हानि होती है कि इनश्योरेंस कम्पनीज़ जो लोन निजी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को देती है उसमें बेड डेट्स होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष बेड डेट्स के रूप में कितनी हानि होती है, इसका पूरा विवरण इस सदन में रखना चाहिये कि किस-किस साल में किस-किस पार्टी ने (**व्यवधान**)

श्री सभापति: अब आपका सवाल ठीक हो गया है।

श्री राम अवधेश सिंह: यह तो मैं भूमिका बता रहा हूं। अब मैं क, ख और ग प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: आपका सवाल सीधा है कि कितना इन्होंने राइट आफ किया है।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं इसको सिलसिलेवार कर दूं, इससे इनको जवाब देने में सुविधा होगी। (**व्यवधान**) मैं भूमिका दे दूं।

श्री सभापति: कितनी देर लगायेंगे आप?

श्री राम अवधेश सिंह: मैं भूमिका बता रहा हूं। मैं पहला सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं जिसका भाग "अ" है।

श्री सभापति: वह तो हो गया।

श्री राम अवधेश सिंह: हुआ नहीं, अभी तो मैंने भूमिका बताई है। मेरे प्रश्न का भाग "क" यह है कि इनश्योरेंस कम्पनीज़ द्वारा दावे के भुगतान में कितनी

रकम दी जाती है और फर्ज़ी नुकसान के दावे के भुगतान में कितनी रकम दी जाती है? मेरे प्रश्न का भाग "ख" यह है कि प्रतिवर्ष कितना कर्ज़ जनरल इनश्योरेंस कम्पनी द्वारा निजी और पब्लिक सेक्टर कम्पनीज़ को दिया जाता है? प्रश्न का भाग "ग" यह है कि दोनों क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक कम्पनियों को दिये गये कर्ज़ में से कितनी राशि बेड डेट्स की है जिसे माफ करना पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी पिछले पांच वर्षों का पूरा सेक्टर-वाइज़ विवरण प्रस्तुत करें। दूसरा सप्लीमेंटरी बाद में पूछूंगा।

श्री दलबीर सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसको वह खुद नहीं समझ पा रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री सभापति: मैं आपको बता देता हूं। उनका सवाल है कि आपने कितना बेड डेट राइट आफ किया है? **(व्यवधान)**

श्री दलबीर सिंह: इसमें यह है कि जी०आई०सी० खास कर के नेचुरल केलेमिटीज़ के लिए, रायट्स के लिए और एविएशन के लिए इनश्योरेंस करती है। लास्ट तीन वर्ष में जो इसमें हमने कम्पनसेशन दिया है **(व्यवधान)**

श्री सभापति: राइटिंग आफ के बारे में पूछ रहे हैं **(व्यवधान)** You have not written off anything?

श्री दलबीर सिंह: राइट आफ का मतलब नहीं है। **(व्यवधान)** इस क्वेश्चन से इसका मतलब ही नहीं है **(व्यवधान)**

श्री सभापति: क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, सीधी बात है। **(व्यवधान)**

श्री दलबीर सिंह: अंडरराइटिंग में प्रोफिट भी होता है और लॉस भी होता है **(व्यवधान)**

MR. CHARIMAN: How much have you paid for underwriting losses? Simple question. Simple answer is required. यह बुहत लम्बा चौड़ा बोलते हैं इसकी वजह से प्रोब्लम हो जाता है। सिम्पल क्वेश्चन यह है कि how much have paid for underwriting losses. That is all.

श्री दलबीर सिंह: 1973 से 1983 तक जी० आई० सी० के अन्तर्गत कोई अंडरराइटिंग लॉस नहीं हुआ। केवल 1984 में दिल्ली में जो रायट्स हुए उनका हमने कम्पनेसेशन दिया है जो 30 करोड़ का है। यह मैं हैवी अमाऊंट बता रहा हूं। दूसरा जो 1986 में आंध्र प्रदेश में फ्लड आया था उसके लिए हमने किया लगभग 15 करोड़ रुपये, इसी तरह से इंडियन एयरलाइंस में जो क्रेश हुआ उसमें हमने 24 करोड़ किया। 1989 में इंडियन एयरलाइंस में फिर जो क्रेश हुआ उसमें हमने 85 करोड़ किया। 1990-91 में जो ए०पी० में साइक्लोन आया उसमें 78 करोड़ किया और आई०पी०सी०एल० में जो फायर एक्सीडेंट हुआ उसमें हमने किया 35 करोड़ रुपये। यह हमारा जो अंडर राइटिंग.....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: वे उतना ही पूछ रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह: यह तो हमारा बुक लास है इसके बावजूद भी हमने प्राफिट किया है।

श्री सभापति: वह तो आपने कह दिया कि ओवर आल फायदा हुआ.....**(व्यवधान)** आपने पूछा था कि अंडर राईटिंग.....**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: मेरा सवाल सीधा है। हानि दो तरह से होती है। दो काम इंश्योरेंस कम्पनी के होते हैं एक तो किसी के दावे का इंश्योरेंस करती है। अगर कोई हानि होती है या सामान का नुकसान होता है तो दावा किया जाता है। जो दावे किये जाते हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इसमें जेनुइन को देना तो सही है लेकिन फर्जी डाक्यूमेंट प्राप्त करके, इन कोनाइवेंस विद द आफिसर्स आफ द इंश्योरेंस कम्पनी जो पे करते हैं उसमें कितनी रकम है। एक पार्ट। दूसरा बैंकिंग की तरह से ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस करते हैं, लोन देते हैं, उसमें इन्होंने कितना अभी तक राइट आफ किया है पिछले 5 साल में। उसमें कितनी रकम है वह मैं पूछ रहा हूं।

श्री दलबीर सिंह: सर, इसके लिए सेपरेट नोटिस माननीय सदस्य दें।

(व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह: यह इससे जुड़ा हुआ है। मंत्री महोदय को इतनी तो तैयारी करके आनी चाहिए। हानि की बात बता रहे हैं तो टोटल, ओवर आल कितनी हो रही है और.....

श्री सभापति: ओवर आल तो फायदा हो रहा है.....**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: मैं कह रहा हूं कि हानि हो रही है, आई चैलेंज हिज स्टेटमेंट।

श्री सभापति: उनका कहना है कि आपने गलत कहा है कि नुकसान हो रहा है।

श्री राम अवधेश सिंह: यह इनको बताना चाहिए कि.....

श्री सभापति: मैं इसमें फैसला नहीं कर सकता हूं। आप कहते हैं कि ओवर आल नुकसान हो रहा है, वे कहते हैं कि फायदा हो रहा है ओवर आल।

श्री यशवन्त सिन्हा: वे फिगर क्यों नहीं बता रहे हैं, अंडर राइटिंग का वे फिगर तो बतायें।

श्री राम अवधेश सिंह: लोन कितना दिया है यह बताइये। बैड डेट के रूप में कितना आपने राइट आफ

कर दिया और यह बताइये कि किन-किन पार्टियों का डेट आपने राइट आफ किया है, यह सूचना दीजिए कि वे बैड डेट वाले हैं या नकली दिवालिया हो गये...**(व्यवधान)** नकली मिल करके....

श्री सभापति: जवाब तो पढ़ा करें। इसमें लिखा है: The underwriting losses in these four years were so much. Even in these four years the Corporation has earned net profits amounting to Rs. 12.89 crores, Rs. 52.62 crores, Rs. 69.46 crores and Rs. 88.68 crores. So, the answer is there.

श्री यशवन्त सिन्हा: किसका किसका अंडर राइट किया है वह पूछ रहे हैं। उसका जवाब दें।

श्री सभापति: यू हैव सेड हियर एण्ड...**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: किसका किया। यही तो पूछ रहा हूं। किस किस पार्टी का किया है लोन। आप तो यह बात बता रहे हैं कि यह इंश्योरेंस कम्पनी का आपको घाटा था लेकिन जो लोन दिया उसका कितना राइट आफ किया, किस किस पार्टी का किया, वे जेनुइन थीं या फर्जी थीं, आपके अफसरों ने मिलकर उनसे कमीशन खाकर कर दिया...**(व्यवधान)**

WELCOME TO HIS EXCELLENCY DR. SAM NUJOMA, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to make an announcement.

As the hon. Members are aware, His Excellency Dr. Sam Nujoma, President of the Republic of Namibia is currently on a State visit to India.

I am glad to inform the House that His Excellency Dr. Sam Nujoma, President of the Republic of Namibia is now seated in the special box to watch the proceedings of this hon. House.

On my own behalf and on behalf of the Honourable Members of the House, we extend a warm welcome to His Excellency Dr. Sam Nujoma. We wish him a happy and fruitful sojourn in our country. We also wish to convey our greetings to the Parliament and the friendly people of the Republic of Namibia.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सभापति जी, राष्ट्रीयकृत...**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: मान्यवर,...**(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सभापतिजी, मुझे बोलने दिया जाए। मुझे यह डिस्टर्ब मत करें।...**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: मैं केवल एक बात पूछूंगा।

श्री सभापति: नहीं, आपके दो प्रश्न हो गये थे। एक अंडर-राइटिंग का हो गया था और दूसरा भी हो गया था।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के राइट-आफ हुए हैं, उनके बारे में क्या सरकार सी०बी०आई० द्वारा जांच करवायेगी कि वह माफ करने लायक थे कि नहीं थे? यह बिल्कुल क्लियर और सीधा सवाल है, पिनप्वाइंटेड सवाल है।...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: वह जवाब तो आपको मिल गया है। ....**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: क्या जवाब आया?

श्री दलबीर सिंह: उसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री राम अवधेश सिंह: इसमें नोटिस की क्या जरूरत है? हमारा पूछना है कि आप सी०बी०आई० द्वारा जांच करवायेंगे या नहीं?

श्री सभापति: यह जनरल नहीं होती है। आप स्पेसिफिक केस दोगे, तो उसके बारे में जांच करा लेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह: नहीं मैंने तो कहा कि क्या सूची है? मैंने प्रश्न में पूछा है कि आपने जिनको माफ किया है, उनकी सूची दीजिए और उनकी जांच करवाइये जिनके कर्ज माफ किये गये हैं क्या वह सही है या उन्होंने अफसरों से मिल कर के राइट-आफ करवाया है?

श्री सभापति: उन्होंने ठीक कह दिया — हरेक केस में सी०बी०आई० इन्क्वायरी — यदि आप कोई स्पेसिफिक केस बतायेंगे, तो वह उनकी जांच करवा लेंगे।

श्री दलबीर सिंह: आपके पास यदि कोई स्पेसिफिक केस हो, तो वह भेज दें। मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सभापति जी, बीमा निगम और उसकी चारों सहायक कंपनियों की ओर से क्या पिछली सरकार ने कोई राजभाषा सम्मेलन आयोजन करने का निश्चय किया था और उसे क्या स्थगित कर दिया गया था और वर्तमान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति में क्या यह प्रस्ताव फिर आया था कि राजभाषा सम्मेलन सारी बीमा कंपनियों का अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन की तरह करने की कोई योजना है और अगर कोई है, तो वह कब तक पूरी होगी और वह कहां होगा और किस रूप में उसमें

वित्त मंत्रालय आयोजन करना चाहते हैं — यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: सम्मेलन बनारस में होना चाहिए।

SHRI V. GOPALSAMY: Irrelevant! Highly irrelevant!

श्री दलबीर सिंह: सम्मानीय पाण्डेय जी ने जो कहा है, उसका अभिवादन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिक कार्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की हाल में हुई बैठक में प्रश्न उठा था, और उसमें श्री शंकर दयाल सिंह जी ने और माननीय डा० रमाकर पाण्डेय जी ने भी एल०आई०सी० समेत इंशोरेंस कंपनीज़ का हिन्दी सम्मेलन करवाने के लिए कहा था। हम जरूर सम्मेलन करवायेंगे, और जहां आप तय कर लें, वहीं पर सम्मेलन करवायेंगे।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, what I want to know from the Government is whether, consistent with its policy of surrendering national interests to foreign interests, the Government is going to permit foreign insurance companies to come into India and how soon... *(Interruptions)*...What happened to the reply?... *(Interruptions)*...

SHRI KAMAL MORARKA: It is a complicated question....*(Interruptions)*....

SHRI YASHWANT SINHA: What happened to the reply, Sir?

श्री सभापति: आपने पूछा कि विदेशी कंपनियां कब आने देंगे। उन्होंने कहा कि यह क्वश्चन नहीं है।

SHRI N.K.P. SALVE: It doesn't arise.

श्री यशवन्त सिन्हा: क्या कहा उन्होंने?

श्री सभापति: उन्होंने कहा कि यह क्वश्चन नहीं है। जब उनके पास दर्खास्त आयेगी, तब वह गौर करेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा: अभी इनके पास कोई दर्खास्त नहीं है। आपके पास अभी कोई दर्खास्त है कि नहीं?...**(व्यवधान)**

श्री सभापति: क्या विदेशी कंपनियों ने इंशोरेंस के लिए दर्खास्त की है और आप उस पर विचार कर रहे हैं?...

श्री एन०के०पी० साल्वे: वह रैलेवेंट नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Are there some applications pending? Are you considering them? That is all.

SHRI DALBIR SINGH: No, Sir. A separate notice is required.

SHRI YASHWANT SINHA: How can there be a separate notice for everything?

SHRI KAMAL MORARKA: The GIC will start making losses.

श्री यशवन्त सिन्हा: यह कैसे चलेगा, सर।...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, अमरीका ने जो नोटिस दिया है यू०एस० ट्रेड लॉ 301 के मातहत उसने यह सवाल भी रखा है कि एंश्योरेंस में, बैंक्स में, दूसरी चीजों में उनको आने दिया जाएगा, इसलिए यह रेलेवेंट क्वश्चन है। तो मैं दो बिंदुओं पर मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पहला यह कि उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? दूसरा, कि यह जो जवाब दे रहे हैं क्या आई०एम०एफ० से पूछ कर दे रहे हैं या बिना पूछे हुए दे रहे हैं?

SHRI DALBIR SINGH: It is not relevant

श्री चतुरानन मिश्र: सर, रेप्लायी होना चाहिए। कुछ भी तो रेप्लायी हो।

Modernisation of Country's Telecommunication System

*2. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to modernise the country's telecommunication system; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYANAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) Statement is placed on the Table of the House.

Statement

To modernise the telecommunication services in the country, the draft 8th Plan proposals include:

— full automatisation of network by March, 1994.

— replacement of life expired and worn-out equipment by electronic equipment.

— provision of additional 3000 route kilometres of ducts for underground cables.

— practically all new equipment proposed for induction during the